February 2026

Uttarakhand Disaster and Accident Analysis Initiative - UDAAI

Social Development for Communities (SDC) Foundation
Dehradun, Uttarakhand
www.sdcuk.in

© 2025 SDC Foundation

SDC Foundation is a Dehradun based environmental action and advocacy group committed to make a positive impact and secure a sustainable future for our home state Uttarakhand, the Himalayas and beyond.

Material from this publication can be used with due acknowledgement.

Editors
Anoop Nautiyal
Prerna Raturi
Gautam Kumar

Research Team
Riya Raj
Misbah Khan
Shubhransh Vir
Praveen Upreti

Contact: SDC Foundation 69, Vasant Vihar,
Dehradun, Uttarakhand (India) - 248001
Website: www.sdcuk.in
Email: contactsdcuk@gmail.com

About UDAAI Monthly Reports

Uttarakhand Disaster and Accident Analysis Initiative (UDAAI) is a monthly initiative by Dehradun-based environmental action and advocacy group, Social Development for Communities (SDC) Foundation. The goal of the UDAAI reports is to document disasters and accidents in Uttarakhand, leading to human and ecological casualties. UDAAI is based on media reports in respectable publications in English and Hindi newspapers, as well as news portals. UDAAI neither attempts nor claims to document all disasters and all accidents in Uttarakhand; its focus instead is to document major casualties and non-casualty events on a regular basis.

We strongly believe that with the perils of inclement climate and unabated disasters, the ecologically fragile and earthquake-prone state of Uttarakhand needs to take many more steps to increase its disaster preparedness. We therefore see UDAAI as a document that highlights attention towards the urgent need for a holistic disaster management and accident minimisation policy framework in Uttarakhand.

It is our earnest hope that UDAAI will spur political leadership, policy makers, bureaucracy, research and academic institutions, businesses, civil society organisations, media and the citizenry at large to initiate inclusive, regular and action-oriented conversations on the subjects of resilience, mitigation and adaptation in Uttarakhand. With mainstreaming and a greater focus on the issue, there is likely to be an improvement in the planning of climate actions and disaster management in Uttarakhand.

Summary of UDAAI Report - February 2026

February 2026 was a line-up for ongoing after-effects of disasters in Uttarakhand where delays for recovery and environmental vulnerabilities in Uttarakhand have continued to determine life in affected areas. In the areas of Maldevta and Sahasradhara near Dehradun, several villages were still in distress months after it had rained extensively in the monsoon season.

Basic infrastructure such as drinking water systems were yet to be restored leaving pipelines, tanks and filtration units damaged or not working. As a result, residents used the most improvised means by inserting plastic pipes into the natural springs to meet daily needs. The surrounding landscape echoed the magnitude of destruction, with debris covered houses, damaged bridges, and so on, and unsafe roads. Although the authorities did work on clearing debris and stabilising embankments, things still progressed slowly.

Scientific developments also singled out the fragility of the Himalayan region. In a research study by the Wadia Institute of Himalayan Geology, the fatal landslides were traced to geological conditions and rainfall patterns. It said that the landslides often occurred in areas close to the seismically sensitive Main Central Thrust fault where weak rock formations are created by small earthquakes. The entrance of rainwater into such fractures enhances the hazards of slope failure path especially under longer duration rainfalls.

Meanwhile in Jyotirmath, people who have been affected by land subsidence renewed their demand for compensation and rehabilitation. Delays in resettlement, outstanding questions of land valuation and lack of a clear safety plan continued to hamper recovery efforts.

Taken together, these developments bear out the reality of delayed rehabilitation, fragile geology and increasing environmental pressures in the intersection of the disaster landscape in Uttarakhand. Addressing these challenges will require the recovery measures to be implemented in a timely manner, further strengthening infrastructure planning, as well as closer linking of scientific research to development-related decisions in the ecologically fragile Himalayan region.

1. February 11, 2026: Disaster turns into calamity: Systemic lethargy causes suffering

Dehradun. The villages of the Maldevta and Sahasradhara areas are still reeling from the disaster that struck five months ago, but now the sluggishness of the system is causing fresh pain. The drinking water crisis in these villages is deepening.

In these villages, located just eight to twenty kilometers from the city, the water supply system's water lines, tanks, chambers, and filter systems are in ruins. Villagers are forced to quench their thirst by burying plastic pipes directly into natural springs. On Tuesday, when the Hindustan team visited villages ranging from Majada, Karligad, Shera, Chamasari to Dhantushera, Chhamroli, Sinyari, and Phulet, the situation appeared dire.

Traversing rocky roads is fraught with difficulties: From Majada, Karligad, Shera, and Chamasari in Sahasradhara to Dhantushera, Chhamroli, Sinyari, and Phulet in Maldevta, numerous houses and bridges are buried under rubble. Piles of debris are piling up in the rivers. Government machinery is busy removing embankments, retaining walls, and debris. The roads are in poor condition, making traversing the rocky roads fraught with difficulties.

HINDUSTAN Feb 11, 2026

पांच माह बाद भी मालदेवता-सहस्रधारा के गांवों में पानी का सिस्टम ध्वस्त, स्रोत से प्यास बुझा रहे लोग, स्कूलों में भी बनी है दिक्कत

आफत बनी आपदा: सिस्टम की सुस्ती से सितम

ग्राउंड रिपोर्ट

■ चांद मोहम्मद

देहरादून। मालदेवता और सहस्त्रधारा क्षेत्र के गांवों में पांच माह पहले आई आपदा के जख्म अब भी हरे हैं, लेकिन अब सिस्टम की सुस्ती यहां के लोगों को नया दर्द दे रही है। इन गांवों में अब पीने के पानी का संकट गहरा रहा है।

शहर से महज आठ से बीस किमी की दूरी पर स्थित इन गांवों में जल संस्थान की पानी की लाइनें, टैंक, चैंबर और फिल्टर सिस्टम ध्वस्त पड़े हैं। ग्रामीण प्लास्टिक के पाइप सीधे खालों (प्राकृतिक स्रोतों) में डालकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। मंगलवार को 'हिन्दुस्तान' टीम ने जब मजाडा, कार्लीगाड, शेरा, चामासारी से लेकर धंतुशेरा, छमरोली, सिन्यारी और फुलेत तक का दौरा किया, तो हालात बदतर नजर आए।

पथरीली सड़कों से गुजरना दुश्वारियों से भरा: सहस्त्रधारा के मजाड़ा, कार्लीगाड, शेरा, चामासारी से लेकर मालदेवता के धंतुशेरा, छमरोली, सिन्यारी, फुलेत तक कई घर, पुल मलबे में दबे हैं। नदियों में मलबे के ढेर जमा है। जहां तहां सरकार की मशीनरी पुश्ते, सुरक्षा दीवारें और मलबा हटाने के काम में लगी है। सड़कों का हाल बुरा है, पथरीली सड़कों से गुजरना दुश्वारियों भरा है।

दून में सहस्रधारा के मजाड़ा गांव में इस तरह टूटी पड़ी हैं पानी की लाइनें। हिन्दुस्तान

देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र के शेरा गांव में पानी न आने से सूखे पड़े हैं नल। हिन्दुस्तान

गुरुजी घर से ला रहे पानी, छात्र स्रोत से ढो रहे बाल्टियां

आईटी पार्क से करीब आठ किमी दूर शेरा गांव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का पुश्ता आपदा में टूट गया था, जो खतरे का सबब बना हुआ है। प्रिंसिपल राकेश भट्ट और शिक्षक सचिन पंवार बताते हैं कि स्कूल में 25 छात्र-छात्राएं और पांच शिक्षक हैं। पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। शिक्षिका पुष्पा लखेड़ा, अल्का सिंह और शिक्षक बलवंत मनराल अपने घरों से पीने के लिए पानी लाते हैं। वहीं, शौचालय और अन्य कार्यों के लिए बच्चे पास के स्रोत से पानी भरकर लाते हैं।

खाले से पानी पीना कार्लीगाड़ के लोगों की मजबूरी बना

कार्लीगाड़ में करीब 30 परिवारों के 200 लोग रहते हैं। दिनेश सिंह, सुभाष रावत और शांति रावत बताते हैं कि पूरा सिस्टम ठप है। प्रधान राकेश जवाडी ने पाइप तो दिए, लेकिन फिल्टर के बिना सीधे खाले से पानी पीना मजबूरी है। ग्रामीण इन पाइपों की रखवाली खुद करते हैं। पाइप हट जाने या पानी कम होने पर उन्हें ठीक करने के लिए डेढ़ किमी ऊपर जाना पड़ता है।

■ आपदाग्रस्त क्षेत्रों की सड़कों का बुरा हाल होने से भी लोग हैं परेशान

■ शेरा के माध्यमिक विद्यालय का टूटा पुश्ता भी खतरे का सबब बना है

लोग बोले-गर्मी में स्रोत सूखेंगे, तब क्या होगा?

मालदेवता के शेरकी, पीपीसीएल और सरखेत से ऊपर सड़कों का हाल बुरा है। आठ किमी ऊपर धंतुसेरा में पवनी देवी, उनके जेठ जयसिंह पंवार और सरिता देवी ने बताया कि सरोना से नीचे खाले में पाइप डाल रखा है, लेकिन अब पानी बहुत कम हो गया है। ग्रामीणों को डर है कि फरवरी के बाद जब स्रोत सूखेंगे, तब क्या होगा? विभाग का डोमकोट स्थित टैंक और चैंबर अब तक ठीक नहीं हुआ है।

भगद्वाडी के इंटर कॉलेज में भी पानी की परेशानी

सिन्यारी के प्रधान महादेव भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सूरत नेगी ने बताया कि पांच महीने बीतने के बाद भी लाइनें ठीक नहीं हुईं। सिन्यारी और फुलेत में वैकल्पिक व्यवस्था से काम चल रहा है, लेकिन भगद्वाडी राजकीय इंटर कॉलेज तक में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। चमरौली, क्यारा, बेस्वाड और फुलेत के लोग भी इसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं।

08 किमी दूर है आईटी पार्क से शेरा गांव, फिर राहत में देरी से लोग परेशान

धंधा भी हुआ मंदा, टैंकर से खरीदना पड़ रहा पानी

शेरा से आगे नूडल्स की दुकान चलाने वाले 65 वर्षीय मदन सिंह चौहान कहते हैं कि लाइनें टूटने से धंधा भी मंदा है। सड़क पर काम कर रहे ठेकेदार 1500 रुपये का टैंकर मंगाते हैं, उसी से वे भी कुछ पैसे देकर ड्रम भरवा लेते हैं। चामासारी, बसवाल, नगदवान, खलैंटी, पटाली, पटेरू और सिलकोटी जैसे गांवों के भी यही हालात हैं। मजाड़ गांव की 75 वर्षीय दिलदेई बताती हैं कि टैंक क्षतिग्रस्त हैं और पाइप जगह-जगह से फट चुके हैं।

कार्लीगाड़ से डेढ़ किमी दूर जाना पड़ता है पानी के लिए

शेरा गांव में 66 वर्षीय बुजुर्ग भगवान देई, गीता और सुभाष बताते हैं कि विभाग ने जो प्लास्टिक के पाइप दिए थे, उन्हें सीधे गदेरे (स्रोत) में डाल दिया है। पानी इतना खराब है कि कपड़े धोने पर साबुन तक फट जाता है। पीने का साफ पानी लाने के लिए कार्लीगाड़ लाइन से एक-डेढ़ किमी दूर जाना पड़ता है, वहां भी पानी दूसरे-तीसरे दिन ही मिल पाता है। किसान बलबीर सिंह भी इस समस्या से बेहद परेशान हैं।

2. February 19, 2026: The number of deadly landslides in the state has increased in 23 years

Dehradun. The number of fatal landslides is increasing in the state. This information has come to light in a study by the Wadia Institute of Himalayan Geology. The study included the cause of landslides, type of rock, slope, weather, and other aspects.

Landslides and other natural disasters occur in the state, resulting in loss of life and property. Damage has often been caused by construction done without prior knowledge of the dangers, and by excessive and heavy rainfall in a short period of time. Along with efforts to reduce the effects of disasters in the state, studies are also underway to understand the causes. The Wadia Institute has studied 64 fatal and reported landslides in the state from 1868 to 2023, in which 1516 people died.

राज्य में 23 वर्षों में जानलेवा भूस्खलन की घटनाएं बढ़ीं

भूकंप से पहाड़ हो रहे कमजोर, बारिश से हो रहा भूस्खलन, 64 घातक भूस्खलन में 1516 लोगों की जान गई

विजेंद्र श्रीवास्तव

देहरादून। राज्य में जानलेवा भूस्खलन की संख्या बढ़ रही है। यह जानकारी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के अध्ययन में सामने आई है। अध्ययन में भूस्खलन का कारण, चट्टान के प्रकार, ढलान, मौसम समेत अन्य पहलुओं को शामिल किया गया।

राज्य में भूस्खलन समेत अन्य प्राकृतिक आपदा आती हैं, इसमें जानमाल का नुकसान होता है। कई बार खतरे की अनदेखी कर किए गए निर्माण और कम समय में अधिक व तेज बरसात के कारण भी नुकसान बढ़ा है। प्रदेश में आपदा के प्रभावों को कम करने के प्रयासों के साथ ही कारणों जानने के लिए भी अध्ययन चल रहा है। वाडिया संस्थान ने राज्य में 1868 से 2023 में आए जानलेवा और रिपोर्ट हुए 64 भूस्खलनों का अध्ययन किया है, जिसमें 1516 लोगों की मृत्यु हुई।

नीस चट्टानों में अधिक भूस्खलन की घटनाएं

वैज्ञानिकों ने भूस्खलन और चट्टानों के प्रकार को लेकर जानकारी जुटाई है। इसमें पता चलता कि सबसे अधिक अधिक घटनाएं नीस (19) और क्वार्टजाइट चट्टानों (14) वाले पहाड़ों में अधिक हुई है। इसके अलावा लाइमस्टोन वाले पहाड़ में भी घटनाएं हुईं। इस अध्ययन में वैज्ञानिक यशपाल सुंदरियाल, अनिरुद्ध चौहान व समीक्षा कौशिक शामिल रहे। इसका पेपर हाल में इंडियन अकादमी साइंस के जर्नल आफ अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित हुआ।

67% घटनाएं वर्ष-2000 के बाद हुई

अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 67 जानलेवा भूस्खलन और लगभग 84 प्रतिशत अत्यधिक वर्षा की घटनाएं वर्ष 2000 के बाद हुई हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सबसे ज्यादा जानलेवा 52 लैंडस्लाइड मानसून (जून से सितंबर) के दौरान हुए। वर्ष-2017 में सर्वाधिक पांच घातक भूस्खलन हुए।

खास खबर

बड़ी भूस्खलन की घटनाएं

18 अगस्त 1998 को पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन हुआ था, इसमें 210 लोगों की मृत्यु हुई। 1880 में नैनीताल में भूस्खलन से 151, अगस्त-1951 में रुद्रप्रयाग जिले के शिवनंदी गांव में 100, अगस्त- 1998 में मद्महेश्वर घाटी में हुए भूस्खलन 103 लोगों की मृत्यु हुई थी। जुलाई-1990 में नीलकंठ क्षेत्र में 100 लोगों की मृत्यु हुई।

भूकंप व बारिश से संबंध

अध्ययन में सामने आया है कि अधिकांश भूस्खलन भूकंपीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मेन सेंट्रल थ्रस्ट के आसपास के क्षेत्रों में हुए हैं। वैज्ञानिक संदीप कहते हैं कि यहां पर छोटे-छोटे भूकंप भी आते हैं। यह भूकंप चट्टानों को कमजोर कर देते हैं और चट्टानों के जोड़ों के बीच की पकड़ को ढीला कर देते हैं। इसके बाद जब बारिश होती है तो पानी इनमें प्रवेश करता है जिससे टूटने की घटना बढ़ जाती है। यह टूटने की घटनाएं कम या अधिक गहरी हो सकती है। हल्के भूस्खलन की घटना 24 घंटे से कम समय तक होने वाली बारिश के समय होते हैं जबकि बड़े भूस्खलन 48 से 72 घंटे तक बारिश होती है तब होते हैं। यह भूस्खलन बारिश के पैटर्न में बदलाव के साथ-साथ बढ़ते ग्राउंड वॉटर लेवल से भी प्रभावित होते हैं।

3. February 20, 2026: Disaster-affected Jyotirmath residents seek action on official promises more than two years after subsidence

More than two years after land subsidence first hit Jyotirmath, the affected locals have submitted a memorandum addressed to chief minister Pushkar Singh Dhami demanding prompt and effective action to address the situation and problems still being faced by the locals.

The memorandum submitted by the Joshimath Bachao Sangharsh Samiti to the sub-divisional magistrate stated that about two and a half years after land subsidence first hit Jyotirmath, the major demands including resettlement of the affected families, compensation and other issues have not been acted upon with the disaster affected families still waiting for rehabilitation.

The government has not taken any action despite the locals repeatedly raising issues including value of the affected land, value of commercial buildings, PMAY and other issues affecting the disaster- affected directly. The Sangharsh Samiti has listed seven major demands including fixing the compensation for commercial damage caused by the disaster as per the discussion held between the committee and chief minister and fixing the value of the land to speed up rehabilitation of the affected persons and selection of the land for resettlement of the affected families.

With stabilisation and safety work not being completed for Jyotirmath, the locals further demanded that a transparent detailed project report for the safety of the town should be implemented. Joshimath Rachao Sangharsh Samiti coordinator Atul Sati and others were also present on the occasion.

Disaster-affected Jyotirmath residents seek action on official promises more than two years after subsidence

PIONEER NEWS SERVICE ■ Jyotirmath

More than two years after land subsidence first hit Jyotirmath, the affected locals have submitted a memorandum addressed to chief minister Pushkar Singh Dhami demanding prompt and effective action to address the situation and problems still being faced by the locals. The memorandum submitted by the Joshimath Bachao Sangharsh Samiti to the sub-divisional magistrate stated that about two and a half years after land subsidence first hit Jyotirmath, the major demands including resettlement of the affected families, compensation and other issues have not been acted upon with the disaster affected families still waiting for rehabilitation. The government has not taken any action despite the locals repeatedly raising issues including value of the affected land, value of commercial buildings, PMAY and other issues affecting the disaster-affected directly. The Sangharsh Samiti has listed seven major demands including fixing the compensation for commercial damage caused by the disaster as per the discussion held between the committee and chief minister and fixing the value of the land to speed up rehabilitation of the affected persons and selection of the land for resettlement of the affected families. The ban on construction in the area following the disaster has caused a major problem for the locals and considering this there should be a uniform rule for governmental and private constructions, the committee said. With stabilisation and safety work not being completed for Jyotirmath, the locals further demanded that a transparent detailed project report for the safety of the town should be implemented. Local unemployed persons should be given priority for working in such works, they said. Joshimath Bachao Sangharsh Samiti coordinator Atul Sati and others were also present on the occasion.

PIONEER

FEBRUARY 20, 2026

About Social Development for Communities (SDC) Foundation

SDC Foundation is a Dehradun-based environmental action and advocacy group engaged in communication, citizen engagement and capacity building in the Himalayan state of Uttarakhand. The foundation works in partnership with institutions of Government of India, Government of Uttarakhand and other stakeholders such as research & academic institutions, community groups, civil society, media partners, NGOs, businesses & trade bodies, schools & colleges in the state.

Climate and environment conservation, waste management, sustainable urbanisation and a basket of sustainable development issues are key focus areas of the foundation.

Anoop Nautiyal,
Founder, SDC Foundation
Dehradun, Uttarakhand
Email: anoop.nautiyal@gmail.com

PS: Errors or omissions in UDAAI documentation, if any, are purely unintentional. In case any errors or key omissions are detected or any fresh updates are available for events that are already documented, SDC Foundation may kindly be notified at the email address contactsdcuk@gmail.com. We shall make the necessary corrections in subsequent versions of the monthly reports of UDAAI.